



दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

खबर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया



भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई गति, 21 अक्टूबर को भारत आए डोनाल्ड टस्क



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026। भारत और पोलैंड के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 से 23 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण

क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को भी आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। 22 अक्टूबर को मोदी-टस्क वार्ता, संबंधों को होगी समीक्षा, प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की भारत यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली वार्ता प्रमुख कूटनीतिक कार्यक्रम होगी। दोनों नेता भारत-पोलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा

वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। भारत और पोलैंड ने अगस्त 2024 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान संबंधों को नई दिशा देने पर सहमति बनी थी। वर्तमान यात्रा इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए अवसर तलाशने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षा, निवेश और आधुनिक तकनीक पर रहेगा जोर इस यात्रा में आर्थिक और औद्योगिक पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वहां के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री अंद्रिज डोमान्स्की और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आएंगे। व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी से दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच संवाद बढ़ाने और निवेश की संभावनाओं की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, संभावित सहयोग और वास्तविक समझौतों के बीच अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है। किसी नए निवेश, रक्षा समझौते या परियोजना की पुष्टि संबंधित आधिकारिक घोषणाओं के बाद ही की जा सकेगी। बेंगलुरु में भारत-पोलैंड व्यापारिक

संवाद इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बेंगलुरु होगा, जहां प्रधानमंत्री टस्क सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र सहित विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, भारत-पोलैंड बिजनेस फोरम 22 अक्टूबर को नई दिल्ली और 23 अक्टूबर को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दोनों देशों के कंपनियों को कारोबारी अवसरों, निवेश और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा के लिए मिल सकता है। इसी तरह पोलैंड की कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति को देखते हुए यह संवाद कर्नाटक के उद्योग जगत के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारतीय कंपनियों को पोलैंड के बाजार और यूरोपीय कारोबारों नेटवर्क के साथ संभावित साझेदारी तलाशने का अवसर मिल सकता है। भारतीय कंपनियों को पोलैंड के बाजार और यूरोपीय कारोबारों नेटवर्क के साथ संभावित साझेदारी तलाशने का अवसर मिल सकता है। भारतीय कंपनियों को पोलैंड के बाजार और यूरोपीय कारोबारों नेटवर्क के साथ संभावित साझेदारी तलाशने का अवसर मिल सकता है।

भी देखा जा रहा है। पोलैंड मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, जबकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर तालमेल से दीर्घकालीन लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। हालांकि, इन संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने के लिए ठोस परियोजनाओं, नियमित कारोबारी संवाद और नीतिगत सहयोग की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री संवाद तथा आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि चर्चाओं को किस हद तक व्यावहारिक समझौतों और दीर्घकालीन साझेदारियों में बदला जाता है।

भारतीय बाजार में एप्पल की छलांग, पहली बार 1.03 लाख करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

लाख करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026। भारत में आईफोन और एप्पल के अन्य उत्पादों की बढ़ती मांग का असर कंपनी के कारोबार पर साफ दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-



26 में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का परिचालन राजस्व 31 प्रतिशत बढ़कर 1,03,853 करोड़ रुपये पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 79,060 करोड़ रुपये था। कंपनी का शुद्ध मुनाफा भी 66 प्रतिशत बढ़कर 5,311 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 3,196 करोड़ रुपये था। कंपनी के ये आंकड़े रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल वित्तीय दस्तावेजों पर आधारित मीडिया

रिपोर्टों में सामने आए हैं। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल करना भारत में एप्पल के कारोबार के विस्तार का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। आईफोन की मांग और प्रीमियम फोन बाजार से मिला सहारा भारत में स्मार्टफोन बाजार के प्रीमियम

खंड की ओर उपभोक्ताओं का रुझान एप्पल के लिए अहम साबित हुआ है। कंपनी के आईफोन के साथ मैकबुक, आईपैड और अन्य उत्पाद भी उसके भारतीय कारोबार का हिस्सा हैं। बाजार में ब्रांड की मजबूत पहचान, उत्पादों की उपलब्धता और प्रीमियम उपकरणों की मांग ने कंपनी की वृद्धि में योगदान दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में भारत में एप्पल की स्मार्टफोन बिक्री की मात्रा में वृद्धि दर 24 प्रतिशत रही, जो पिछले वित्त वर्ष के 11 प्रतिशत के स्तर से दोगुने से भी अधिक है। मुनाफे में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 66 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। वित्त वर्ष

2025-26 में मुनाफा 5,311 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 3,196 करोड़ रुपये था। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी ने कारोबार बढ़ाने के साथ अपनी कमाई में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। हालांकि, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों के आधार पर वृद्धि के सटीक कारणों का अलग-अलग आकलन जरूरी है। राजस्व और शुद्ध मुनाफा अलग-अलग वित्तीय मानक हैं और दोनों को एक ही अर्थ में नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की मौजूदगी ऐसे समय में मजबूत हुई है, जब प्रमुख मोबाइल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज है। उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और महंगे स्मार्टफोन की बढ़ती स्वीकार्यता कंपनियों की रणनीति को प्रभावित कर रही है। एप्पल इंडिया के ताजा वित्तीय आंकड़े बताते हैं कि भारतीय बाजार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। आने वाले समय में कारोबार की रफ्तार बनाए रखने के लिए उत्पादों की उपलब्धता, कीमत, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता अहम कारक रहेंगे।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन पर अभिजीत दीपके का विराम, समर्थकों से बोले— परिवार के साथ बिताएं समय

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को कांक्रिक जनता पार्टी (सोजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने फिलहाल रोकने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो संदेश में उन्होंने समर्थकों से त्योहारों के दौरान परिवार के साथ समय बिताने और उनका ध्यान रखने की अपील की। इस दौरान पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के जेल में होने का जिक्र करते हुए दीपके भावुक हो गए। दीपके के संदेश के अनुसार, सौरभ दास और आशुतोष रांका की कानूनी परेशानियों ने उन्हें आहत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आंखों में आए आंसू डर का संकेत नहीं, बल्कि साथियों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव का परिणाम हैं। उन्होंने दोनों को अपना भाई बताते हुए कहा कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद आंदोलन से जुड़े लोगों का मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। परिवार के साथ रहें, लेकिन अपने उद्देश्य को न भूलें। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दिए गए लगभग छह मिनट के संदेश



गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर उन लोगों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। दीपके ने भावुकता को कमजोरी मानने की धारणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके लिए संवेदनशीलता ही ताकत है। उन्होंने यह भी कहा कि सौरभ दास और आशुतोष रांका के बाहर आने पर वे उसी मुस्कान के साथ आगे बढ़ेंगे और गांधीवादी रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। उनके मुताबिक, कठिन परिस्थितियों के बावजूद

नफरत के बजाय प्रेम और अहिंसा की भावना बनाए रखना जरूरी है। दोनों प्रवक्ताओं की हिरासत और कानूनी कार्रवाई चर्चा में इस करे वालों के लिए अपने प्रियजनों का साथ और देखभाल भी जरूरी है। उन्होंने महात्मा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाए जाने के बाद कथित अनधिकृत प्रवेश से जुड़े मामले को पुलिस की अपराध शाखा को स्थानांतरित किया गया। मामले में कर्नाट प्लेस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223ए, 332 और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जांच अब अपराध शाखा करेगी। इन धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों और मामले को परिस्थितियों पर अंतिम निष्कर्ष जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकाला जा सकेगा। आंदोलन पर विराम, आगे की रणनीति पर नजर अभिजीत दीपके की घोषणा से मुख्य चुनाव आयुक्त रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। उनके मुताबिक, कठिन परिस्थितियों के बावजूद

राहुल गांधी चार दिन के वियतनाम दौर पर, INDIA गठबंधन के प्रदर्शनों में विराम; भाजपा ने साधा निशाना

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चार दिन के दौरे पर वियतनाम रवाना हुए हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में सक्रिय INDIA गठबंधन ने त्योहारों के सप्ताह को देखते हुए अपने विरोध प्रदर्शनों को फिलहाल विराम दिया है। राहुल गांधी पिछले दो सप्ताह से इन प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। उनके विदेश दौरे को लेकर भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं, जबकि विपक्ष चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। पार्टी नेताओं के अनुसार, राहुल गांधी चार दिनों तक विदेश में रहेंगे। वियतनाम रवाना होने से पहले वह रविवार को गोवा में कांग्रेस की गौरव रक्षण यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके दौरे को लेकर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। भाजपा नेताओं ने विदेश दौरे पर उठाए सवाल भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर



खंडेलावाल ने भी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी विदेश यात्राओं, वहां होने वाली मुलाकातों और उनके खर्च के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी देनी चाहिए। उनके अनुसार, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गतिविधियों को लेकर जनता का सवाल पूछना स्वाभाविक है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. चुनावी पारदर्शिता को लेकर INDIA गठबंधन के प्रदर्शन राहुल गांधी पिछले दो सप्ताह से दिल्ली में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रहे। इन प्रदर्शनों में कांग्रेस सहित INDIA गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं और सांसदों ने भाग लिया। विपक्ष ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की जांच और जवाबदेही की मांग उठाई है। हालांकि, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी से संबंधित आरोपों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्यों से अलग समझना जरूरी है। त्योहारों के

कारण प्रदर्शनों पर अस्थायी विराम INDIA गठबंधन ने त्योहारों के सप्ताह को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में अपने नियमित विरोध मार्च फिलहाल रोक दिए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवाल उनके राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। त्योहारों के बाद इन मुद्दों पर आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में उपलब्ध जानकारी में कोई विस्तृत कार्यक्रम सामने नहीं आया है। राहुल गांधी के विदेश दौरे और प्रदर्शनों में विराम का एक ही समय पर सामने आना राजनीतिक चर्चा का विषय बना है। हालांकि, केवल समय के संयोग के आधार पर दौरे और प्रदर्शन रोकने के फैसले के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। गोवा में गौरव रक्षण यात्र में हुए थे शामिल वियतनाम रवाना होने से पहले राहुल गांधी गोवा में कांग्रेस की गौरव रक्षण यात्रा में शामिल हुए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह यात्रा 22 सितंबर को शुरू हुई और 18 अक्टूबर को संपन्न हुई। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए राज्य की जमीन, पहचान, पर्यावरण और सांस्कृतिक

विरासत की रक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए। पार्टी ने जमीन के उपयोग में बदलाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे विषयों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। राज्य की सभी 40 विधानसभा सीटों तक पहुंचने की योजना वाले इस अभियान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और स्वतंत्र पुष्टि के आधार पर ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। राहुल गांधी का वियतनाम दौरा जहां भाजपा के निशाने पर है, वहीं चुनावी पारदर्शिता को लेकर विपक्ष की मांगों भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि त्योहारों के बाद INDIA गठबंधन इन मुद्दों पर अपना अभियान किस रूप में आगे बढ़ाता है।

नागोया में भारत का स्वर्णिम निशाना, मोना अग्रवाल ने बनाया गेम्स रिकॉर्ड; अवनि लेखरा को रजत

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नागोया, 21 अक्टूबर 2026। जापान के आजी-नागोया में आयोजित एशियन

प्रतियोगिता में देश की मजबूत शुरुआत की। 0.4 अंक के अंतर से मोना ने मारी बाजी फाइनल मुकाबले में मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा के बीच कड़ा

निशानेबाजी की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाती है। अवनि लेखरा ने भी बढ़ाया देश का मान अवनि लेखरा ने रजत पदक जीतकर एक बार फिर अपनी प्रतिभा और निरंतरता का परिचय दिया। इससे पहले उन्होंने 2022 के हांगझोउ एशियन पैरा गेम्स में इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इस बार रजत पदक के साथ उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन की निरंतरता बनाए रखी। मोना और अवनि की संयुक्त सफलता भारतीय खेल जगत के लिए विशेष महत्व रखती है। एक ही स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीतना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय पैरा खिलाड़ों विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं।

मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की मिसाल मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा की उपलब्धियां उन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा हैं, जो चुनौतियों के बावजूद खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। पैरा खेलों में खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा के साथ शारीरिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण, तकनीक और मानसिक तैयारी पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। निशानेबाजी जैसे खेल में एकग्रता, संतुलन और दबाव के बीच सटीक निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। फाइनल में दोनों भारतीय

खिलाड़ियों के बीच बेहद कम अंतर इस स्पर्धा के उच्च प्रतिस्पर्धात्मक स्तर को भी दर्शाता है। भारतीय पैरा खेलों के लिए उत्साहजनक शुरुआत एशियन पैरा गेम्स 2026 का आयोजन 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आजी-नागोया में हो रहा है। प्रतियोगिता में एशिया के विभिन्न देशों के पैरा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे बड़े मंच पर भारत के लिए शुरुआती पदक हासिल करना उत्साहजनक है। मोना अग्रवाल का रिकॉर्ड स्वर्ण और अवनि लेखरा का रजत पदक भारतीय दल के मनोबल को बढ़ाने वाली उपलब्धियां हैं। इन सफलताओं से उम्मीद है कि प्रतियोगिता के आगामी मुकाबलों में भी भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश की पदक तालिका को मजबूत करेंगे। दोनों निशानेबाजों की उपलब्धि केवल पदकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेलों में समान अवसर, प्रतिभा और निरंतर प्रयास के महत्व को भी रेखांकित करती है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश में पैरा खेलों के प्रति जागरूकता और प्रोत्साहन बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। मोना अग्रवाल का रिकॉर्ड स्वर्ण और अवनि लेखरा का रजत पदक भारत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। नागोया में भारतीय निशानेबाजों की इस सफलता ने एशियन पैरा गेम्स में देश के अभियान को शानदार शुरुआत दी है।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम जारी किए। नई टीम में सात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन राष्ट्रीय महासचिव और सात राष्ट्रीय सचिवों सहित विभिन्न पदों पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार की विधायक और प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। पार्टी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ये नियुक्तियां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार की गई हैं और तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। नई टीम में विभिन्न राज्यों के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सात नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर जम्मू-कश्मीर की विधायक शगुन परिहार, पश्चिम बंगाल के विधायक सोमन करफा, उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी, नगालैंड के अरविंद दमान्नी, तेलंगाना की मालोथा कोमाली नाइक, बिहार के राजेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र नाग को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में ओडिशा की अर्पिता अपराजिता बदेजेना, उत्तर प्रदेश के हर्षवर्धन सिंह और आंध्र प्रदेश

के मिश्रा वामशी कृष्णा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सात राष्ट्रीय सचिव भी नियुक्त



भाजपा युवा मोर्चा की नई टीम में राष्ट्रीय सचिव के पद पर असम के बिस्वजीत खोंड, मध्य प्रदेश के आशीष झाला, महाराष्ट्र की सायली रघुनाथ कुलकर्णी, राजस्थान के हिमांशु शर्मा, पंजाब के सरदार अरमानजोत बराड़, झारखंड के अमन यादव और बिहार के राहुल झा को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के विनीत वत्स त्यागी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजस्थान के देवव्रत सिंह राजावत को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारियां भी तब बिहार के हिमांशु यादव को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली की शिवानी सिंह

और विशु बसोया तथा हिमाचल प्रदेश के अतुल ठाकुर को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी



गई है। दिल्ली की अपूर्वा सिंह राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में काम करेंगी, जबकि बिहार के मानवेंद्र चौहान को सह-प्रभारी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से हैं। नई नियुक्तियों के साथ भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन में विभिन्न राज्यों के नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। नई नियुक्तियों को पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से पांच सदस्य शामिल किए गए हैं। बिहार, गुजरात, केरल, मध्य

प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से दो-दो सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिला है। शेष 17



सदस्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दार्द्रा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से हैं। नई नियुक्तियों के साथ भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन में विभिन्न राज्यों के नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। नई नियुक्तियों को पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से पांच सदस्य शामिल किए गए हैं। बिहार, गुजरात, केरल, मध्य

सम्पादकीय

ऋषभदेव से महावीर तक जिन धर्म की एकता, फिर पंथवाद क्यों? आत्ममंथन का समय

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

जैन धर्म की पहचान उसकी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम, तप और आत्मशुद्धि की साधना से रही है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक तीर्थंकरों की शिक्षाओं ने मनुष्य को आत्मविजय, करुणा, विवेक और नैतिक जीवन का मार्ग दिखाया। इन शिक्षाओं का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था को अभिव्यक्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के विचार, व्यवहार और जीवनशैली को परिकृत करना भी है। ऐसे में जैन समाज के भीतर पंथगत मतभेदों, धार्मिक पहचान और सामाजिक दूरी को लेकर उठने वाले प्रश्न गंभीर विचार की मांग करते हैं। मोटेदेखने मास्टर्स–चैतन्य चेतना जागृति मंच के प्रस्तुतकर्ता नीरज सिंघवी ने इसी संदर्भ में समाज से आत्ममंथन करने और जिन धर्म के मूल सिद्धांतों को प्राथमिकता देने की अपील की है। मूल प्रश्न किसी एक पंथ या परंपरा के पक्ष अथवा विपक्ष में खड़े होने का नहीं है। मूल सवाल यह है कि क्या धार्मिक विविधता के बीच सामाजिक एकता, पारस्परिक सम्मान और साझा मूल्यों को पर्याप्त स्थान मिल रहा है? यदि धर्म का उद्देश्य आत्मकल्याण और जीवन का परिकार



है, तो धार्मिक मतभेद आपसी संवाद के बजाय दूरी का कारण क्यों बनें? इन प्रश्नों पर शांतिपूर्वक विचार करना आज जैन समाज के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक जीवन के लिए भी प्रासंगिक है। पंथों की विविधता और साझा विरासत का महत्व जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं के साथ अनेक उपपरंपराएं विकसित हुई हैं।इनकी मान्यताओं, साधु-जीवन, आमम साहित्य, प्रतिमा-पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इतिहास में इन परंपराओं के विकास के पीछे धार्मिक व्याख्याओं, साधना-पद्धतियों और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका रही है। भद्रबाहु और स्थूलभद्र से जुड़ी परंपराओं का उल्लेख भी जैन इतिहास की चचाओं में मिलता है, हालांकि इन घटनाओं के विवरण और कालक्रम को लेकर विद्वानों के बीच विभिन्न व्याख्याएं हैं। इस ऐतिहासिक विविधता को केवल विभाजन के रूप में देखना उचित नहीं होगा। धार्मिक परंपराओं का विकास समय के साथ होता है और अलग-अलग समुदाय अपने विश्वाओं तथा साधना-पद्धतियों को विशिष्ट रूप में संरक्षित करते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब अपनी परंपरा के प्रति निष्ठा दूसरे की परंपरा के प्रति असम्मान में बदलने लगे। अपनी मान्यताओं का पालन करना धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन दूसरी मान्यताओं को तुच्छ समझना या सामाजिक संबंधों में भेदभाव का आधार बनाना किसी भी स्वस्थ समाज के हित में नहीं है। इसलिए आवश्यकता पंथों को समाप्त करने की नहीं, बल्कि पंथगत विविधता के बीच साझा धार्मिक मूल्यों को मजबूत करने की है। एकता का अर्थ सभी मतभेदों को मिटा देना नहीं, बल्कि मतभेदों के बावजूद एक-दूसरे को सम्मान देने की क्षमता विकसित करना है। अहिंसा और अनेकतावाद की कसौटी पर धार्मिक व्यवहार जैन दर्शन का अहिंसा सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं है। विचार, वाणी और व्यवहार में संयम भी इसके व्यापक नैतिक संदेश से जुड़ा है। इसी प्रकार अनेकतावाद यह समझने की प्रेरणा देता है कि किसी विषय को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। यह सिद्धांत संवाद, सहिष्णुता और बौद्धिक विनम्रता को प्रोत्साहित करता है। यदि इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में उतारा जाए, तो धार्मिक मतभेदों के कारण पैदा होने वाली कटुता को कम किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान केवल इस बात से नहीं आंकी जानी चाहिए कि वह किस परंपरा में विश्वास रखता है या किस पद्धति से पूजा करता है। उसके आचरण, सत्यनिष्ठा, करुणा, संयम और दूसरों के प्रति व्यवहार को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। हालांकि, पूजा-पद्धतियों और धार्मिक अनुष्ठानों को महत्वहीन मानना भी उचित नहीं होगा। अनेक श्रद्धालुओं के लिए ये परंपराएं उनकी आस्था, साधना और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग हैं। प्रश्न पूजा करने या न करने का नहीं, बल्कि पूजा के साथ उसके नैतिक संदेश को जीवन में उतारने का है। धार्मिक कर्मकांड और आचरण परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए; उनकी सार्थकता तब बढ़ती है, जब वे व्यक्ति को आर्थिक संवेदनशील, अनुशासित और जिम्मेदार बनाते हैं। अपरिग्रह का संदेश और धार्मिक आयोजनों में सादगी जैन दर्शन का अपरिग्रह सिद्धांत संग्रह की प्रवृति पर संयम रखने और आवश्यकताओं के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। वर्तमान समय में धार्मिक आयोजनों, सामाजिक समारोहों और सार्वजनिक प्रतिष्ठ से जुड़े खर्चों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। धार्मिक आयोजनों की भव्यता अपने आप में अनुचित नहीं है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं, परंपराओं को जीवित रखते हैं और सामूहिक सहभागिता का अवसर प्रदान करते हैं।लेकिन जब दिखावा, प्रतियर्था या अनावश्यक खर्च उनके मूल उद्देश्य पर हावी होने लगे, तब आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है। धार्मिक संसाधनों का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवदया और सामाजिक कल्याण जैसे कार्यों में लगाने पर भी विचार किया जा सकता है।

गुरुवाणी से सामाजिक बदलाव की राह: कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सामूहिक संकल्प जरूरी



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

समाज की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक समृद्धि, शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी आंकी जाती है कि वह अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर करने और मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए कितना गंभीर है। बाल विवाह, कन्या विक्रय, मृत्युभोज और अनावश्यक सामाजिक खर्च जैसी कुप्रथाएं लंबे समय से अनेक समुदायों के सामने चुनौती रही हैं।इनसे मुक्ति के लिए कानून, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के कलबी समाज में गुरुवाणी के माध्यम से सामाजिक सुधार की पहल इसी संदर्भ में विचारणीय है। प्राप्त विवरण के अनुसार, पावन तीर्थधाम शिकारपुरा के आराध्य गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री राजाराम जी महाराज ने लगभग एक शताब्दी पूर्व समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया था। इनमें बाल विवाह, कन्या

विक्रय और मृत्युभोज जैसी प्रथाओं को छोड़ने पर विशेष जोर बताया गया है। वर्तमान गादीपति महंत श्री श्री 108 श्री दयाराम जी महाराज के मार्गदर्शन में इन शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार और सामाजिक सुधार के प्रयास किए जाने की जानकारी सामने आई है। अब लूणी पटेल पट्टी के पंच-पटेलों से भी इन संदेशों को सामूहिक रूप से अपनाने की अपील की जा रही है। यह पहल एक व्यापक प्रश्न उठाती है—क्या धार्मिक आस्था और सामाजिक नेतृत्व की शक्ति का उपयोग समाज को रूढ़ियों से मुक्त करने, जरूरतमंद परिवारों का बोझ कम करने और नई पीढ़ी के लिए बेहतर वातावरण बनाने में किया जा सकता है? इसका उत्तर सकारात्मक हो सकता है, बशर्ते ऐसे प्रयास संवाद, सहमति, मानवीय संवेदनशीलता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हों। गुरुवाणी की प्रासंगिकता और सामाजिक सुधार की परंपरा भारतीय समाज में संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने समय-समय पर नैतिक जीवन, सेवा, सदाचार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। धार्मिक उपदेशों का महत्व तब और बढ़ जाता है, जब वे लोगों को केवल जागरूकता के साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के कलबी समाज में गुरुवाणी के माध्यम से सामाजिक सुधार की पहल इसी संदर्भ में विचारणीय है। प्राप्त विवरण के अनुसार, पावन तीर्थधाम शिकारपुरा के आराध्य गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री राजाराम जी महाराज ने लगभग एक शताब्दी पूर्व समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया था। इनमें बाल विवाह, कन्या

मणिपुर में शांति की चुनौती: हिंसा का अंत, न्याय की शुरुआत और विश्वास की बहाली जरूरी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

मणिपुर में हिंसा और जनहानि की खबरें एक बार फिर देश के सामने गंभीर सवाल खड़े करती हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता केवल कानून बनाने या सुरक्षा बलों की तैनाती से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि नागरिक स्वयं को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें न्याय मिलने का कितना भरोसा है और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास किस हद तक कायम है। मणिपुर की चुनौती भी इसी कसौटी पर परखी जानी चाहिए। यहां स्थायी शांति स्थापित करना केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक सद्भाव से जुड़ा व्यापक दायित्व है। हिंसा की प्रष्ठभूमि और शांति की जटिल चुनौती मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का ऐसा राज्य है, जहां विविध समुदायों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं हैं। यहां जातीय पहचान, भूमि, संसाधनों, प्रतिनिधित्व और सुरक्षा से जुड़े प्रश्न लंबे समय से संवेदनशील रहे हैं।मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा ने इन चुनौतियों को गंभीर मानवीय संकट में बदल दिया। हिंसा के दौरान लोगों की जान गई, घर

और संपत्तियां नष्ट हुईं तथा बड़ी संख्या में परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। ऐसे संघर्षों के प्रभाव केवल घटनास्थल तक सीमित नहीं रहते। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, रोजगार छूटता है, कारोबार प्रभावित होता है और परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती है। लंबे समय तक असुरक्षा का वातावरण बने रहने से लोगों के मन में भय और दूसरे समुदायों के प्रति अविश्वास भी गहरा सकता है।इसलिए हिंसा की किसी नई घटना को अलग-थलग देखने के बजाय उसके व्यापक सामाजिक और मानवीय प्रभावों को समझना आवश्यक है। किसी भी राज्य में शांति स्थापित करने की पहली शर्त नागरिकों की सुरक्षा है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, समय पर खुफिया जानकारी का उपयोग और संपावित तनाव को रोकने के लिए प्रभावी प्रशासनिक समन्वय जरूरी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की सफलता तभी स्थायी परिणाम दे सकती है, जब आम नागरिकों को यह विश्वास हो कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी अपराध की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। हिंसा के मामले में कार्रवाई करते समय किसी समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराने से

सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, किसी भी ऐतिहासिक उपदेश की व्याख्या और उसके प्रभाव का आकलन करते समय प्रामाणिक विवरणों को महत्व देना आवश्यक है। सामाजिक सुधार की पहल को मजबूत बनाने के लिए गुरुवाणी के संदेशों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, उनके व्यावहारिक अर्थ समझना और समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ना उपयोगी होगा। मृत्युभोज: परंपरा और आर्थिक विवेक के बीच संतुलन किसी परिवार में मृत्यु होना गहरे दुख का समय होता है।ऐसे अवसर पर परिजनों को भावनात्मक सहारें, सामाजिक सहयोग और संवेदना की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि सामाजिक दबाव के कारण शोकग्रस्त परिवार को बड़े भोज, दिखावे या अनावश्यक खर्च के लिए बाध्य होना पड़े, तो यह स्थिति उसकी पीड़ा को और बढ़ा सकती है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ऐसे खर्च कर्ज और वित्तीय परेशानों का कारण बन सकते हैं।इसलिए मृत्युभोज जैसी प्रथाओं पर पुनर्विचार करना सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है। शोक के अवसर पर परिवार के साथ खड़े होना, जरूरत के अनुसार सहायता करना और दिवंगत व्यक्ति की स्मृति में सेवा कार्य करना अधिक संवेदनशील विकल्प हो सकते हैं। यह बदलाव किसी परिवार पर दबाव डालकर नहीं, बल्कि जागरूकता और सामूहिक सहमति से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। समाज के प्रभावशाली लोगों और पंच-पटेलों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें तथा किसी परिवार को परंपरा के नाम पर अनावश्यक खर्च करने के लिए बाध्य न होने दें। बाल

विवाह और कन्या विक्रय के विरुद्ध दृढ़ सामाजिक संकल्प बाल विवाह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वतंत्र विकास से जुड़े अवसरों को प्रभावित कर सकता है। इसे रोकना केवल सामाजिक सुधार का विषय नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और कानून के पालन से जुड़ा दायित्व भी है। इसी प्रकार कन्या विक्रय जैसी प्रथा महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के प्रतिकूल है। समाज में इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं होंगी। परिवारों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों को जागरूक करना होगा। बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन, बेटीयों के प्रति समान दृष्टिकोण, विवाह में सहमति और कानूनी प्रावधानों की जानकारी जैसे कदम बदलाव को स्थायी बना सकते हैं। धार्मिक नेतृत्व और सामाजिक पंचायतें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यदि वे स्पष्ट रूप से बाल विवाह और कन्या विक्रय का विरोध करें, तो सामाजिक स्वीकार्यता में बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, ऐसे मामलों में कानून के अनुरूप कार्रवाई और प्रभावित लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है। लूणी पटेल पट्टी से व्यापक समाज तक बदलाव की संभावना गुरुवाणी प्रचारक किसान राम पटेल ने लूणी पटेल पट्टी के नहीं, बल्कि जागरूकता और सामूहिक सहमति से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। समाज के प्रभावशाली लोगों और पंच-पटेलों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें तथा किसी परिवार को परंपरा के नाम पर अनावश्यक खर्च करने के लिए बाध्य न होने दें। बाल

चितलवाड़।, जालोर, आहोer, गुड़ामालानी, सिवाना, समदड़ी और बालोतरा सहित पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों तथा उत्तरी गुजरात के थराद, धानेरा, पालनपुर और मेहरसाणा में भी गुरुवाणी के प्रचार-प्रसार का उल्लेख किया गया है। इन क्षेत्रों में सामाजिक सुधार की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। पंचायतों की बैठकों में कुरीतियों पर चर्चा, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी, सामूहिक संकल्प-पत्र, विवाह एवं शोक समारोहों में सादगी को प्रोत्साहन और जरूरतमंद परिवारों की सहायता जैसे उपाय व्यावहारिक साबित हो सकते हैं। यह भी जरूरी है कि किसी पहल की सफलता का आकलन केवल सभाओं या घोषणाओं की संख्या से न हो। वास्तविक परिवर्तन तब दिखाई देगा, जब परिवारों पर अनावश्यक खर्च का दबाव घटेगा, बच्चों की शिक्षा सुरक्षित होगी और सामाजिक निर्णयों में महिलाएं भी तथ्या युवाओं की आवाज को उचित स्थान मिलेगा। संपादकीय दृष्टिकोण: परंपरा का सम्मान, कुरीतियों से मुक्ति परंपराएं समाज की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होती हैं, लेकिन हर पुरानी प्रथा को बिना विचार किए जारी रखना आवश्यक नहीं है।समय के साथ समाज का दायित्व है कि वह अपनी परंपराओं की मानवीय उपयोगिता का मूल्यांकन करे। जो परंपराएं सहयोग, करुणा, सेवा और सद्भाव बढ़ाती हैं, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए; वहीं जो प्रथाएं आर्थिक बोझ, भेदभाव या किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें प्रभाव और जागरूकता बढ़ने की बात कही गई है। सांचोर, रानीवाड़।,

प्रक्रिया में निर्णायक हो सकती है। उनके निर्णयों में पारदर्शिता, समानता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। सामाजिक अनुशासन के नाम पर किसी परिवार का अपमान या बहिष्कार करने के बजाय समझाइश, सहयोग और जागरूकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धार्मिक आस्था का सबसे सकारात्मक उपयोग वही है, जो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करे और समाज में न्यायपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा दे। निष्कर्ष: गुरुवाणी का सम्मान, व्यवहार में बदलाव से शिकारपुरा धाम से जुड़ी गुरुवाणी के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की अपील एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय है। यदि इस संदेश को व्यापक सहमति, व्यावहारिक कार्यक्रमों और निरंतर जनजागरण का आधार बनाया जाए, तो यह समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में योगदान दे सकता है। लूणी पटेल पट्टी के पंच-पटेलों के सामने यह अवसर है कि वे सामाजिक नेतृत्व की केवल परंपराओं के निर्वहन तक सीमित न रखकर शिक्षा, समानता, आर्थिक विवेक और मानवीय गरिमा की रक्षा से जोड़ें।यही पहल दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। गुरुवाणी की सच्ची सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब उसके उपदेश जीवन में दिखाई दें—बाल विवाह रुके, कन्या के सम्मान की रक्षा हो, मृत्युभोज के अनावश्यक दबाव से परिवार मुक्त हों और समाज सेवा, सहयोग तथा सद्भाव की दिशा में आगे बढ़े। सामाजिक सुधार किसी एक व्यक्ति या संगठन का कार्य नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। संकल्प, संवेदना और सतत प्रयास से ही कुरीतियों से मुक्त, जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण संभव है।

मणिपुर में शांति की चुनौती: हिंसा का अंत, न्याय की शुरुआत और विश्वास की बहाली जरूरी

बचना चाहिए। जिम्मेदारी उन व्यक्तियों की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राहत शिविरों में रह रहे परिवारों की आवश्यकताओं का नियमित आकलन होना चाहिए और बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। घर वापसी केवल लोगों को उनके मूल स्थान तक पहुंचाने का नाम नहीं है। इसके लिए सुरक्षा की वास्तविक गारंटी, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत, आजीविका की बहाली और पड़ोसियों के बीच विश्वास कायम करना भी जरूरी है। जहां परिस्थितियां अनुकूल हों, वहां स्वैच्छिक और सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। प्रभावित परिवारों पर जल्द लौटने का दबाव रखने के बजाय उनकी सुरक्षा और सहमति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राजनीतिक इच्छाशक्ति और संवाद की भूमिका मणिपुर में शांति बहाली के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन, नागरिक संगठनों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को समन्वित प्रयास करने होंगे। लोगों ने हिंसा के कारण अपने घर छोड़े, उनके लिए सुरक्षित आवास, भोजन, स्वास्थ्य



तथा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सुरक्षा मिले।विस्थापित परिवारों का पुनर्वास सर्वोच्च प्राथमिकता मणिपुर में स्थायी शांति की चर्चा विस्थापित परिवारों की समस्याओं को नजरअंदाज करके पूरी नहीं हो सकती। जिन लोगों ने हिंसा के कारण अपने घर छोड़े, उनके लिए सुरक्षित आवास, भोजन, स्वास्थ्य

वाले देशों पर संभावित प्रतिबंधों और शुल्कों के माध्यम से दबाव बनाने की नीति पर विचार किया है। हाल के घटनाक्रम में अमेरिकी प्रशासन ने रूस से जुड़े कुछ प्रस्तावित दंडात्मक प्रावधानों को फिलहाल छूट दी है और इस विषय पर आगे समीक्षा की बात कही है। रबियों ने भी माना है कि कुछ देशों के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर तुरंत बढ़ना आसान नहीं होता। भारत के लिए यह आवश्यक है कि ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हितों, लागत और आपूर्ति की विश्वसनीयता के आधार पर लिए जाएं।रूस से तेल खरीदना हो या अन्य देशों से ऊर्जा आयात करना, प्राथमिकता देश की जरूरतों और आर्थिक स्थिरता को मिलनी चाहिए। किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है, लेकिन बिना पर्याप्त विकल्प तैयार किए आयात व्यवस्था में अचानक बदलाव करना भी मंश्रा साबित हो सकता है। इसलिए भारत को ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मजबूत करने, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने और दीर्घकालीन आपूर्ति समझौते विकसित करने पर लगातार काम करना चाहिए।इससे वैश्विक राजनीतिक तनावों के बीच देश की निर्णय लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकेगी। कूटनीति में संतुलन, निर्णय में स्वतंत्रता भारत और अमेरिका के संबंध विश्वेश के सफल हैं। रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश, शिक्षा, अनुसंधान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता

जैसे विषय भी दोनों देशों के सहयोग का हिस्सा हैं। ऐसे में व्यापार समझौते को केवल शुल्कों के उतार-चढ़ाव तक सीमित रखना उचित नहीं होगा।दोनों देशों को ऐसा ढांचा विकसित करना चाहिए, जो आर्थिक सहयोग के साथ परस्पर सम्मान और नीतिगत स्पष्टता को भी मजबूत करे। भारत को अमेरिका के साथ सहयोग करना नहीं होना चाहिए। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की ताकत उसकी स्वतंत्र और आर्थिक स्थिरता को मिलनी चाहिए। किसी एक श्रोत पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है, लेकिन बिना पर्याप्त विकल्प तैयार किए आयात व्यवस्था में अचानक बदलाव करना भी मंश्रा साबित हो सकता है। इसलिए भारत को ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मजबूत करने, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने और दीर्घकालीन आपूर्ति समझौते विकसित करने पर लगातार काम करना चाहिए।इससे वैश्विक राजनीतिक तनावों के बीच देश की निर्णय लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकेगी। कूटनीति में संतुलन, निर्णय में स्वतंत्रता भारत और अमेरिका के संबंध विश्वेश के सफल हैं। रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश, शिक्षा, अनुसंधान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता

वास्तविक वृद्धि होती है, रोजगार के विस्तार अवसर बनते हैं, घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कितनी बढ़ती है और उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलता है। साथ ही, यदि किसी क्षेत्र को नुकसान की आशंका हो तो उसके लिए समयबद्ध सहायता और समायोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।निष्कर्ष: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर खोल सकता है, लेकिन उसकी सफलता राष्ट्रीय हितों की रक्षा और दीर्घकालीन आर्थिक मजबूती पर निर्भर करेगी। भारत को बाजार विस्तार के साथ किसानों, छोटे उद्योगों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों का संतुलन बनाए रखना होगा। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भी निर्णय बाहरी दबाव के बजाय राष्ट्रीय जरूरतों और व्यावहारिक विकल्पों के आधार पर होने चाहिए। कूटनीति का उद्देश्य केवल समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि देश के लिए न्यायसंगत और टिकाऊ परिणाम हासिल करना है। भारत-अमेरिका संबंधों की वास्तविक सफलता तभी होगी, जब सहयोग से व्यापार बढ़े, रोजगार के अवसर मजबूत हों, तकनीकी क्षमता विकसित हो और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे। राष्ट्रीय हितों की कसौटी पर निष्पक्ष देखना। समझौता ही दोनों देशों की साझेदारी को दीर्घकालीन मजबूती दे सकता है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: राष्ट्रीय हितों की कसौटी पर कूटनीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता

भारतार्थ खबर

Bhaarataarth.com

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता इस समय दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों के केंद्र में है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रबियो की भारत यात्रा के दौरान व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दे प्रमुखता से चर्चा में हैं। दोनों देशों की ओर से समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति के सकेत मिले हैं। भारत के वाणिज्य सचिव के अनुसार, समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देकर कानूनी मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी। वहीं, रबियो ने भी इसे निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना वाला समझौता बताया है। हालांकि, अंतिम हस्ताक्षर और लागू होने की शर्तों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार महत्वपूर्ण है। इस परिस्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा समझौता सुनिश्चित करना है जो भारतीय उद्योग, किसानों, निर्यातकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए देश की दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता को मजबूत करे। कूटनीतिक सफलता का वास्तविक मूल्यांकन समझौते की सुविधियों से नहीं, बल्कि उसके व्यावहारिक परिणामों से होना चाहिए। व्यापार विस्तार के अवसर और चुनौतियां अमेरिका विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और भारतीय उत्पादों तथा

सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। कपड़ा, परिधान, औषध, इंजीनियरिंग उत्पाद, रब एवं आपूर्ण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों

फायदा केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे।छोटे और मध्यम उद्यमों को भी अमेरिकी बाजार में प्रवेश के लिए तकनीकी सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन, वित्तीय संसाधन और



के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। यदि प्रस्तावित समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच, स्थिर शुल्क व्यवस्था और स्पष्ट व्यापारिक नियम मिलते हैं, तो उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है। इससे उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना भी बनेगी। लेकिन व्यापार समझौते का लाभ तभी व्यापक होगा, जब उसका

आसान निर्यात प्रक्रियाएं उपलब्ध करानी होंगी। भारत के अनेक छोटे उद्योग सीमित पूंजी और ऊंची अनुपालन लागत के कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए सरकार को समझौते के साथ ऐसे सहयोगी उपाय भी तैयार करने चाहिए, जो छोटे उद्यमों को वास्तविक अवसर प्रदान करें। घरेलू उद्योग और किसानों के हित सर्वोपरि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाजार

करना पड़ सकता है। विशेष रूप से कृषि, डेयरी और छोटे विनिर्माण उद्योगों के लिए समझौते की शर्तों का सावधानीपूर्वक आकलन आवश्यक है। भारत की कृषि व्यवस्था केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इसलिए कृषि उत्पादों के आयात, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों और किसानों की आय से जुड़े प्रावधानों पर जल्दबाजी में

तेल आयात और ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत-अमेरिका वार्ता का एक संवेदनशील पक्ष रूस से भारत के कच्चे तेल का आयात भी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में तेल की कीमत, उपलब्धता और आपूर्ति मार्गों में बदलाव का असर परिवहन, बिजली, उद्योग और आम उपभोक्ता की लागत पर पड़ सकता है। अमेरिका ने रूस से ऊर्जा खरीदने

छायाचित्र किशोर दफ्तरी बेंगलुरु

पूणाहति संपन्न

चैलसिंह, ओबसिंह चौहान, नकुलसिंह
दहि या, किशोरसिंह चौहान और
दलपतसिंह भायल सहित समाज के
अनेक पदाधिकारी, गणमायज्यन एवं
श्रदालु उपस्थित रहे। आयोजन में
शामिल समाज के लोगों ने मां चामुंडा के
प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए धार्मिक
परंपराओं के संरक्षण और सामाजिक
एकता को मजबूत बनाने की भावना
दोहराई। मंदिर में संपन्न धार्मिक अनुष्ठानों
ने नवरात्रि के अवसर पर आस्था,
संस्कृति और सामूहिक सहभागिता के
महत्व को रेखांकित किया। समाचार प्रेषक
दलपतसिंह भायल बंगलुरु।

